Feb 2012

vkbZ-vkbZ-,- v/;{k dh dye ls-------------------------------------

भारत के रिटेल क्षेत्र में एफ.डी.आई. विगत कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। भिन्न– भिन्न सेक्टर के लोगों की इस विषय पर राय भी भिन्न–भिन्न है। जहॉ केन्द्रिय सरकार एफ.डी.आई. की पुरजोर वकालत कर रही है वहीं विपक्षी पार्टीयॉ एवं सरकार के कुछ सहयोगी भी इसका विरोध कर रहें हैं। व्यापारिक संगठन इसका सबसे अधिक विरोध कर रहें तथा बड़े औद्योगिक घराने एवं बड़े उद्योगों के संगठन इसका समर्थन कर रहे है। किसानों एवं छोटे उद्योगों के लिए भी रिटेल में एफ.डी.आई. का निर्णय लाभप्रद बताया जा रहा है। परन्तु स्वयं छोटे किसान और छोटे उद्योग इस विषय पर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि वे इस विषय की पूर्ण जानकारी एवं बारिकियों से अनभिज्ञ है।

अतः छोटे उद्योगों के हित में इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने (एम.एस.एम.ई. का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते) ''एफ.डी.आई. का एम.एस.एम.ई. पर प्रभाव'' विषय पर एक विस्तृत चर्चा प्रारम्भ की है ताकि इसके दोनों पहलू छोटे उद्यमियों के सामने सरलता से प्रस्तुत किये जा सकें। इस प्रयास में आई.आई.ए. द्वारा 1 जनवरी 2012 को लॉच किये गये अपने blog में ''एफ.डी.आई.'' विषय पर चर्चा प्रारम्भ कर दी है। हमने यह भी निर्णय लिया कि फरवरी 2012 का आई.आई.ए. न्यूज इसी विषय को समर्पित किया जाए। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आई.आई.ए. के इस अंक में देश के शूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से सम्बन्धित अनेक उपयोगी विचार सामने आए हैं इसके साथ ही अर्न्तराष्ट्रीय अनुभवों पर बेहद दिलचस्प लेख भी प्रस्तुत किया गया है जिनसे आई.आई.ए. को एवं देश के सभी लघु उद्योग संगठनों को इस क्षेत्र के उत्थान में कार्य करने हेतु मार्ग दर्शन प्राप्त होगा।

भारत सरकार ने Single Brand रिटेल में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. बढ़ाने का निर्णय अभी हाल में ले लिया है, Multi Brand Retail में 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. का निर्णय चाहे फिलहाल टाल दिया गया है परन्तु आशंका है कि वर्तमान विधान सभाओं के चुनाव सम्पन्न होने पर सरकार इसको भी लागू कर देगी। यह निर्णय लागू हो या न हो, लघु उद्योग संगठनों का यह कर्तव्य है कि हम लघु उद्यमियों को इस विषय पर समय रहते जागरूक करे और उन्हें इसके लाभ/हानि के लिए तैयार करें। साथ ही हमारा यह भी कर्तव्य है कि लघु उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु सरकारी नियम कानूनों को भी पुखता करवाऍ जैसे कि यदि 30 प्रतिशत सामग्री सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय की जानी है तो यह कैसे सुनिश्चित हो ताकि लघु उद्योग विचैलियों से बच सकें। लघु उद्यमियों द्वारा सप्लाई किए गए माल का मूल्य उन्हें समय से मिल सके। लघु उद्योगो के माल की गुणवत्ता एवं मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हो इत्यादि।

अतः मेरा एम.एस.एम.ई. उद्यमी भाइयों से आग्रह है कि हर स्थिति में अपना मनोबल बनायें रखें एवं विश्वास रखें कि प्रतिकूल को अनुकूल करने की क्षमता हमारे अन्दर ही है।

पाठकों से मेरा अनुरोध है कि आई0आई0ए0 न्यूज के इस अंक में प्रकाशित विभिन्न विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिखते रहे और आई0आइ0ए0 blog (www.iiablog.in) पर भी अपने विचार भेजते रहे।

अगले माह, बजट छाया रहेगा। हमेशा की तरह इस वर्ष भी आई.आई.ए. द्वारा बजट–पूर्व प्रस्ताव वित्त मंत्रालय एवं एम.एस.एम.ई. मंत्रालय को भेजा गया है। देखना यह है कि नये बजट में एम.एस.एम.ई. को प्राथमिकता मिलेगी या एक बार फिर अनदेखा किया जाएगा। मार्च में ही आई.आई.ए. EXPO नोएडा में आयोजित होगा, मैं आशा करता हूँ कि इस EXPO से विशेषतयः एम.एस.एम.ई. क्षेत्र लाभान्वित होगा तथा प्रगति के पथ पर अधिक तीव्रता से अग्रसर हो सकेगा।

शुभकामनाएँ!

t|xy fd’kkj